

47 वर्षों बाद होगा जिला उद्योग केंद्रों का कायाकल्प

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ: राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए 47 वर्षों बाद सभी जिला उद्योग केंद्रों (डीआइसी) का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति के बाद इन्वेस्ट यूपी ने डीआइसी के कायाकल्प की योजना तैयार कर ली है। इसके तहत डीआइसी भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही गेट, प्रशासनिक भवन, कान्फ्रेंस हॉल, आगंतुकों के लिए प्रतीक्षा हॉल, शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा।

केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1978

में सभी जिलों में जिला उद्योग केंद्रों (डीआइसी) की स्थापना की थी। स्थापना के बाद से जिला उद्योग केंद्रों को हमेशा सरकारी दफ्तरों के तरीके से ही व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन की स्वीकृति दी थी। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी के कार्य का दायरा बढ़ाने के लिए 11 महाप्रबंधक (जीएम) व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) के अलावा प्रतिनियुक्त पर पीसीएस संवर्ग के दो संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की भी तैनाती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। वहीं निवेशकों से संवाद स्थापित

करने के लिए इन्वेस्ट ने यूपी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद व चेन्नई में सैटेलाइट कार्यालय खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य में निवेश के लिए आने वाले निवेशकों की सहूलियत के लिए जिला उद्योग केंद्रों के कायाकल्प की योजना को भी मंजूरी मिलने के बाद इन्वेस्ट यूपी ने सभी जिला उद्योग केंद्रों से प्रस्ताव मांगे हैं कि कहां-कहां पर क्या-क्या काम होने वाले हैं। जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों से कहा गया है कि भवनों की मरम्मत, वातानुकूलन, फर्नीचर, कान्फ्रेंस हॉल के साथ कार्यालयों में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके भेजें।